

न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ० भारकर विश्वादी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 04/2019 G.C.M.S. No. 2019/00178 दर्ज दिनांक : 13.03.2019
अपीलाधिगण:

1. शान्ति पुत्र रताजी,
2. बाबु पुत्र सुरताजी,
3. गोवा पुत्र केवाजी,
4. लवजी पुत्र कच्छाजी,
समस्त जातियान कोली, निवासीगण बामनवाड़ा, तहसील रानीवाड़ा,
जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यधिगण:

1. कस्तुरा पुत्र धर्मा फौत के कायम मुकाम:-
1/1 मासूग पुत्र कस्तुरा,
1/2 पोपट पुत्र कस्तुरा,
2. गंगा बेवा रणसाजी,
3. चूना पुत्र रणसाजी,
4. वीरा पुत्र रणसाजी,
5. बलवन्त पुत्र रणसाजी,
6. भैरु पुत्र रणसाजी,
7. मगन पुत्र सूरताजी फौत के कायम मुकाम:-
7/1 वेरसीराम पुत्र मगन,
7/2 सरदारा पुत्र मगन,
7/3 प्रताप पुत्र मगन,
7/4 नेनु पुत्री मगन,
8. पारखान पुत्र सूरताजी के फौत के कायम मुकाम:-
8/1 मावा पुत्र पारखान,
8/2 नारणा पुत्र पारखान,
8/3 वनाराम पुत्र पारखान,
8/4 चन्द्रा पुत्री पारखान,
9. केसा बेवा कच्छाजी फौत के कायम मुकाम:-
9/1 जगसी पुत्र कच्छाजी,
9/2 हरी पुत्र कच्छाजी,
10. पारखान पुत्र रताजी,
11. सौरभ बेवा केवाजी फौत के कायम मुकाम:-
11/1 उम्मेद पुत्र केवाजी,
समस्त जातियान कोली, निवासीगण बामनवाड़ा, तहसील रानीवाड़ा,
जिला जालोर।
12. राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार रानीवाड़ा, जिला जालोर।



राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर, रानीवाड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2006 बअनवान पारखान बनाम कस्तुरा वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 31.08.2006 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार:-

1. श्री जगदीश गोदारा, श्री पारसामल बराड़ा, विद्वान अभिमापक अपीलाण्ट्स।
2. श्री चेनाराम पटेल, श्री प्रवीण कुमार भादरू विद्वान अभिमापक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांक: 31.12.2025

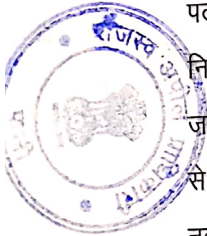
अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर, रानीवाड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2006 बअनवान पारखान बनाम कस्तुरा वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है-

अपीलाण्ट द्वारा अपील के साथ विलम्बकाल माफ करने के लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि अपीलार्थीगण को निर्णय की जानकारी नहीं थी, दिनांक 04.02.2019 को पटवारी हल्का के पास जमाबंदी लेने शान्ति गया तथा अपने खेत की जमाबंदी मांगी तक पटवारी ने बताया कि आपके खेतों का बंटवाड़ा हो चुका है। तब शान्ति न्यायालय में निर्णय की नकल लेने गया तो बताया कि उक्त पत्रावली जिला रेकर्ड शाखा जालोर में जमा हो चुकी है। तब वह दिनांक 05.02.2019 को जालोर आया व जिला रेकर्ड शाखा से अपने अधिवक्ता के मार्फत नकल मांगी जो नकल दिनांक 18.02.2019 को प्राप्त हुई नकल प्राप्त होने पर उक्त बंटवाड़ा आदेश व डिक्री की जानकारी हुई। अतः जानकारी के अनुसार अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर डिले कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है-

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट संख्या 01, 03, 04 एवं रेस्पोंडेंट संख्या 9/1, 9/2, 10, 11/1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण



अपीलाण्ट संख्या 02 व दीगर रेस्पोजेण्ट्स के विरुद्ध वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में एक दावा बाबत बंटवाडा खातेदारी आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत प्रस्तुत किया गया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.2006 को अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गयी। जिसके विरुद्ध अपीलाण्ट्स प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 13.09.2019 को लगभग 12 वर्ष 06 माह अर्थात लगभग 4577 दिवस के अत्यंत दीर्घ विलंब के साथ पेश की गई।

2. अपीलांट प्रार्थीगण द्वारा विलम्ब के कारण रूप में प्रार्थीगण को निर्णय की जानकारी नहीं होना तथा दिनांक 04.02.2019 को प्रार्थी शान्ति पटवारी हल्का के पास जाने तथा जमाबंदी की नकल मांगने पर पटवारी द्वारा दावे का निर्णय के अनुसार हिस्से अलग होना बताने पर जिला कार्यालय से दिनांक 18.02.2019 को नकल प्राप्त होने से जानकारी होने का कथन किया है।

3. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोजेण्ट द्वारा प्रार्थीगण के कथनों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में अपीलाण्ट स्वयं वादी व प्रतिवादी बतौर पक्षकार रहे है। अतः इन्हे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की बखूबी जानकारी रही है। अपीलाण्ट द्वारा जानबूझ कर अत्यधिक विलम्ब से अपील प्रस्तुत की है। जो म्याद बाहर होने से काबिल खारिज है।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील लगभग 12 वर्ष 06 माह अर्थात लगभग 4577 दिवस के अत्यंत दीर्घ विलंब के साथ हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण के गुणावगुण पर इस स्तर पर कोई टिप्पणी किए बिना हमारा विनम्र मत है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट्स संख्या 01, 03 व 04 स्वयं वादी रहे है, तथा अपीलाण्ट्स संख्या 02 प्रतिवादी पक्षकार रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत करने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये जाने तक प्रकरण की बखूबी जानकारी थी। वादीगण पक्षकार द्वारा यह कथन करना की उनके द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में पारित निर्णय व डिक्री लगभगत 12 वर्ष 06 माह तक कोई जानकारी नहीं थी तथा सबसे पहले जानकारी दिनांक 04.02.2019 को पटवारी हल्का के पास जमाबंदी लेने जाने पर तथा पटवारी के कहने पर दिनांक 18.02.2019 को नकल प्राप्त होने पर हुई, पूर्णतया भ्रामक, आधारहीन एवं काल्पनिक कथन है। तथा विलंबकाल अपीलाण्ट्स की उदासीनता व लापरवाही के कारण घटित हुआ है। अपीलाण्ट्स प्रार्थीगण द्वारा दिन-प्रतिदिन के विलंब के कारण दर्शित नहीं किये है। तथा प्रार्थना पत्र में दर्शित विलम्ब के कारण युक्तियुक्त, सद्भाविक व स्वीकार योग्य नहीं हैं।

राजस्व अपील प्राधिकरण

5. विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अधोलिखित प्रकरणों में पारित अभिमत व विनिश्चय अवलोकनीय है :-


1. 2007 (2) RRT 939 (S.C.) – Limitation Act, 1963-Sec. 5- condonation of delay-In-ordinate delay of 3320 days in filing appeal-Delay not properly and satisfactorily explained- Court can not condone the delay on sympathetic grounds-No reason given to condone the inordinate delay-Held, Order is not sustainable and set aside.

2. 2017 (1) RRT 117 (Raj. H.C.) - Limitation Act, 1963-Sec. 5 – Condonation of delay of 2344 days in filing appeal in action or indolence of the part of the litigant- liberal approach can not be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory and otiose – No sufficient cause to explain the delay, Held application and appeal are liable to dismiss.



2024 RBJ 396 (S.C.) – Section 5 & 3 – As the provision of section 3 of limitation act appeal which is preferred after the expiry of limitation is liable to be dismissed. the use of word "shall" in the aforesaid provision connotes that the dismissal is mandatory subject to the exception section 3 of the act is peremptory and had to be given effect to even though no objection regarding limitation is taken by the other side or referred to in the pleadings. In other words, it casts an obligation upon the court to dismiss and appeal which is beyond limitation. This is general rule of limitation.

4. 2024 RBJ 463 (S.C.) – Section 5 - It hardly matters whether a litigant is a private party or a State or Union of India when it comes to condoning the gross delay of more than 12 years- If the litigant chooses to approach the court long after the lapse of the time prescribed under the relevant provisions of the law-then he cannot turn around and say that no prejudice would be caused to either side by the delay being condoned- This litigation between the


राजस्व अपील प्राधिकरण

parties started sometime in 1981- We are in 2024- Almost 43 years have elapsed- However, till date the respondent has not been able to reap the fruits of his decree- It would be a mockery again ask the respondent to undergo the rigmarole of the legal of justice if we condone the delay of 12 years and 158 days and once proceedings- (ii) The question of limitation is not merely a technical consideration- The rules of limitation are based on the principles of sound public policy and principles of equity- We should not keep the 'Sword period of time to be determined at the whims and fancies of the of Damocles' hanging over the head of the respondent for indefinite appellants. Appeal dismissed

6. हमने माननीय न्यायालयों द्वारा उपर्युक्त प्रकरणों में प्रतिपादित अभिमत का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण की प्रकृति व परिस्थितियां उपर्युक्त प्रकरणों के समान है तथा माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त अभिमत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में अविश्वसनीय रूप से 4577 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंब कारित किया है। प्रार्थीगण द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए तथा विलंब के कारणों के रूप में दर्शित आधार विश्वसनीय, युक्तियुक्त व स्वीकार योग्य नहीं होकर वस्तुतः प्रार्थीगण की लापरवाही व घोर उदासीनता के कारण विलंब घटित होना साबित है। साथ ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरुद्ध नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफ किये जाने योग्य नहीं हैं तथा प्रार्थी के साथ किसी भी दृष्टि से उदार रूख अपनाया जाना परिसीमा अधिनियम 1963 के विधिक प्रावधानों व मंशा के विपरीत होगा।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि 4577 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंबकाल माफीयोग्य नहीं होने से प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश


अतः निष्कर्षतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है,

राजस्व अपील प्राधिकारी
करी

फलस्वरूप अपील अपीलांत अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर-ए-इजलास सुनाया गया।




(डॉ० भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली